राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगपतियों और किसानों को दिया गया ऋण

2373. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 से 30 दिसम्बर, 1977 तक देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उद्योगपतियो और किसानों को क्रमशः कितने करोड़ रुपये के ऋण दिए गए ; और

(ख) किसानों को दिए गए कुल ऋण मे से कितने प्रतिशत ऋण उन किसानो को दिया गया जिनके पास पाच एकड़ से कम भूमि है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सितम्बर, 1977 को समाप्त होने वाले छः महीनो के लिये बैंक ऋण के क्षेत्रीय वितरण का सुनिश्चित बैंक समूहवार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं हुआ है । सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमो के क्षेत्रीय वितरण के मार्च 1977 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार त्वरित अनुमान निम्नलिखित हैं —

(करोड़ रुपयो में)

सरकारी क्षेत्र के बैंको का कुल बकाया ऋण	11766
(1) सरकारी खाद्यान्न आसादन	2045
(2) कृषि	1275
(3) छोटे उद्योग	1216
(4) अन्य उपेक्षित क्षेत्र	675
(5) अन्य क्षेत्र [बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योग और थोक व्यापार (खाद्यान्न आसादन के अलावा) और उन्हें दिये गये निर्यात ऋण सहित]	6555

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जोत-क्षेत्रवार ताजे उपलब्ध आंकड़े सितम्बर, 1976 के अन्त तक के हैं। इन्हें नीचे दिया गया है :—

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सितम्बर, 1976 के अन्त तक कृषकों को दिया गया सीधा ऋण

(करोड़ रुपये)

जोत क्षेत्र समूह	खाते	राशि
कृषकों के पास जोत क्षेत्र		
(i) 5 एकड़	18,37,658 (67.2)	248.98 (36.8)
(ii) कुल सीधा ऋण	27,34,794	695.53

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ों से कुल सीधे ऋण से प्रतिशत का पता चलता है)

Staff Sanctioned for Erstwhile Marine Products Export Development Authority

2374. SHRI BALAK RAM: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the total number and Category-wise details of staff sanctioned for the erstwhile Marine Products Export Development Authority;

(b) the total number and category-wise details of staff sanctioned by the Government till-date for the Marine Products Export Development Authority;

(c) the total number and category-wise details of staff sanctioned by the

Authority/Executive Committee or Chairman without reference to Government; and

(d) the number and categories of Class IV posts created by the Authority or Chairman from 1st January, 1975 to 31st August, 1977 inspite of the existing ban?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) to (c). The information is as per Statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1248/77]. Information in regard to part (a) has been furnished under the presumption that it refers to erstwhile Marine Products Export Promotion Council.

(d) One post of Messenger for Regional Office, Calcutta was sanctioned by the Authority with effect from 1st April 1977.

Recommendations of the Pillai Committee

2375. SHRI R. L. KUREEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have accepted the recommendations of the Pillai Committee on Standardisation of Pay Scales, Service Conditions, Service Conduct Rules and Disciplinary Regulations for Officers in the fourteen nationalised banks;

(b) if so, when are they going to be implemented; and

(c) if not, why and to what extent they are rejected?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). Recommendations of the Pillai Committee relate to standardisation of Pay scales, allowances and perquisites of officers in the nationalised banks and not to the Service Conduct Rules and Disciplinary Regulations. The recommendations of the Pillai Committee as modified by the group of bankers have already been accepted by the Government and communicated to the banks concerned for their adoption. Nationalised banks are taking steps for implementing these recommendations

बिहार राज्य के प्रखण्डों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोला जाना

2376. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के कितने प्रखंडों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें नहीं खोली गई है,

(ख) क्या भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई भी शाखा नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सभी प्रखंडों में शाखायें कब तक खोली जायेंगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) दिसम्बर, 1977 की स्थिति के अनुसार बिहार में 94 ऐसे सामुदायिक विकास खंड हैं जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कोई कार्यालय नहीं है ।

(ख) और (ग). आजकल भागलपुर जिले के गोपालपुर खण्ड के लिए कोई बैंक कार्यालय नहीं है। परन्तु, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1977 में लाइसेंस जारी किया था और आशा है वह गोपालपुर में शीघ्र ही अपना कार्यालय खोलेगा । बिहार के शेष बिना बैंक वाले